Dainik Jagran (Bhopal) 19 January, 2017

# खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संजीवनी देने व्यापक खाद्य सुरक्षा आवश्यक

## खेतों से आपूर्ति को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता

व्यापार प्रतिनिधि, भोपाल

अपार संभावनाओं से भरे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिये केन्द्र सरकार को एक व्यापक खाद्य सुरक्षा योजना बनाने की जरूरत है। इस योजना में अंतरराष्ट्रीय परिकल्पनाओं तथा दिशानिर्देशों को शामिल किया जाना चाहिये, ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये कृषि उत्पादों की आपूर्ति को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सके। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) और टारी द्वारा किए गए फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री विषयक अध्ययन में रेखांकित करते हुए कहा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, रसद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने और प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग देकर श्रमिकों की क्षमता बढ़ाने से भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हब बनाने में

खासी मदद मिलेगी। एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डीएस रावत व टारी की निदेशक सुश्री क्षमा कौशिक ने यह अध्ययन रिपोर्ट जारी की।

**मप्र खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भावी नेतृत्वकर्ता :** अध्ययन में यह भी कहा गया है कि मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला मध्य प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, और वह भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में व्यापक योगदान दे सकता है। हालांकि यह चिंताजनक विषय है कि पिछले वित्तीय वर्ष (2015-16) में मध्य प्रदेश द्वारा आकर्षित करीब छह लाख करोड़ रुपए के कुल अदत्त निवेश में से खाद्य एवं कृषि आधारित उत्पाद क्षेत्र का योगदान केवल 3382 करोड़ रुपए का ही रहा।